letter/representation has been received in recent times from the Mazdoor Kishan Shakti Sangathan, (Rajasthan urging for C.B.I, probe into rural development scam of the state.

(c) The amount released to the State of Rajasthan under major rural development/employment schemes viz. Jawahar Rozgar Yojana (JRY), employment Assurance Scheme (EAS) Integrated Rural Development Programme (IRDP), Indira Awaas Yojana (lAY), Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP), Drought Prone Area Programme (DPAP) & Desert Development Pro-granmic (DDP) during last three years is given below:—

Amount released (Rs. in lakhs)

Programme	1994-95	1995-96	1996-97
J.R.Y.	1468078	15060.74	7231.81
E.A.S	9900 00	14030 00	10390.00
I.R.D.P.	2017.03	1969.62	2205.74
	1506 86	5167.49	4032 70
A.R.W.S.P.	8231 00	6908 00	8456 00
DPAP	426 50	643.77	152 00
D.D.P	6450 00	5358 00	1639.91

*includes G.K.Y.

(d) Various types of monitoring mechanism used to review the progress of Rural Development Employment Programmes are, periodical progress reports, review meetings by senior officers, concurrent Evaluation Studies, field visits by senior officers etc. Short comings, if any, observed • are brought to *the* notice of State Governments.

स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता

2442. **श्री राम जेठमलानी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण में निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करने के लिए स्वरोजगार प्रारम्भ करने के इच्छुक नौजवानों को वित्तीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 और 1996-97 में स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए देश के ग्रामीण अंचलो में वित्तीय आवश्यकता की राशि के संबंध में क्या अनुमान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ आवश्यक धनराशि की उपलब्धता हेतु कोई व्यवस्था कायम करने पर भी विचार किया हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : (क) से (घ) स्वरोजगार प्रारम्भ करने के इच्छुक युवकों की वित्तीय आवश्यकता के अनुमान से संबंधित आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इस मंत्रालय के पास गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के संबंध में वर्ष 1992-93 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों

के प्रतिशत का अनुमान हैं। सभन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार उपलब्ध करायार जाता हैं जिसके अंतर्गत सरकार ऋण जुटाने और प्रति परिवार निवेश के बारे में लक्ष्य निर्धारित करती हैं। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए प्रति परिवार निवेश लक्ष्य क्रमशः 14,000 रूपये और 15,000 रूपए था। इसके अलावा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण किया जाता हैं जिससे कि वे प्रशिक्षण के उपरोक्त स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार शुरू कर सके।

गुजरात में लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौघोगिकी समुन्नति परिषद (कपार्ट) योजना

2443. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षो के दौरान लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुलति परिषद योजना के विस्तार तथा प्रचार-प्रसार के उदेश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया हैं;

(ख) तत्संबंधी जिला बार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) राज्य में "कपार्ट" के अंतर्गत जिला-बार कौन-कौन सी योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं तथा कौन-कौन सी योजनाओं को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई;

(घ) क्या "कपार्ट" योजनाओं का प्रसार सही ढंग से नहीं किया गया हैं; और

(ङ) राज्य के आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम को अत्याधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार की क्या योजना हैं।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : (क) से (ग) 1994 में अहमदाबाद में कपार्ट को क्षेत्रीय समिति की स्थापना से कपार्ट गुजरात में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम हुआ हैं। इसके फलस्वरूप कपार्ट द्वारा गुजरात के स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता में निरंतर वृद्वि हुई हैं। विगत 3 वर्षो के दौरान गुजरात में स्वैच्छिक संगठनों की 289 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 1085.44 लाख रूपए हैं। विगत तीन वर्षो के दौरान गुजरात में कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के जिला-वार ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं [देखिए परिशिष्ट 181 अनुपत्र संख्या 65] कपार्ट ने सूचित किया हैं कि स्वीकृत परियोजनाओं को कुल मिलाकर संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया गया हैं/किया जा रहा हैं।

(घ) और (ड.) कपार्ट द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रचारित और लोकप्रिय बनाने के विचार से अहमदाबाद स्थित इसकी क्षेत्रीय समितियां आवश्यकता आधारित परियोजना प्रस्तावों का पता लगाने और बनाने में स्वैच्छिक संगठनों तथा जनजातीय क्षेत्रों के स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करने हेतु समय-समय पर कार्यशालाओं के आयोजन में गुजरात राज्य के प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों को भी शामिल किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त, कपार्ट की गृह पात्रिका में उपलब्धियां प्रकाशित को जाती हैं। इन उपायो के अलावा कपार्ट इस प्रयोजनार्थ आकाशवाणी दूरदर्शन और क्षेत्रीय समाचार पत्रों जैसे मास मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा हैं।

Implementation of land reforms

2444. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the land reforms measures are not being implemented effectively in several States and particularly in Orissa;

(b) if so, the reasons for the tardy piogress of the land reforms measures;